

मारवाड़ का मित्र जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर
मारवाड़ का मित्र
facebook.com/marwarakamitra
visit, Like and share

फेसबुक पेज



संविदा कर्मियों की छंटनी और उठते गंभीर सवाल

राजस्थान के सहकारी बैंकों में संविदा कर्मियों की अचानक छंटनी: श्रम अधिकारों और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल

राजस्थान के सहकारी बैंकों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों की अचानक छंटनी न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि यह श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपेक्स बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक कर्मचारी और वाहन चालक जैसे अनिवार्य पदों पर कार्यरत कर्मियों को जिस तरह बिना किसी प्रक्रिया के बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। सहकारी बैंकों में पिछले चार दशकों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और चालकों जैसे नियमित पदों पर सीधी भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में संस्थाओं के रोजमर्रा के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए इन संविदा कर्मचारियों ने अपने जीवन के कई साल लगा दिए। अब जब राज्य सरकार नियमित भर्तियों की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तब वर्षों से अनुभव हासिल कर चुके इन कर्मियों को अचानक हटा देना किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी पाठदर्शी और कल्याणकारी व्यवस्था में कर्मचारियों की छंटनी के तय नियम होते हैं। श्रम संहिताओं के प्रावधानों को ताक पर रखकर की जा रही यह कार्रवाई कर्मचारी संगठनों के भारी रोष का कारण बनी है। ऑल राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन यूनियन ने इस रवैये को अमानवीय करार देते हुए शासन सचिव सहकारिता और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। जैसलमेर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई हालिया घटना—जहाँ 16 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया और एक पीड़ित कर्मी की मानसिक तनाव से मौत हो गई—यह बताने के लिए पर्याप्त है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। सहकारिता का मूल सिद्धांत ही ‘आपसी सहयोग और कल्याण’ है, लेकिन जब सहकारी बैंक प्रबंधन ही कर्मचारियों के प्रति इतना कठोर और मनमाना रुख अपनाने लगे, तो सहकारी आंदोलन की साख पर धब्बा लगना स्वाभाविक है। यदि समय रहते इस प्रशासनिक मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया गया और अनुभवी संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा नहीं की गई, तो यह असंतोष एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। राज्य सरकार और संबंधित शीर्ष अधिकारियों को चाहिए कि वे मामले की संवेदनशीलता को समझें, छंटनी की इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाएं और पीड़ित कर्मचारियों को न्याय प्रदान करें।



-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं।



सहकारिता में निरंतर गठित कागजी कमेटियां पैक्स के निर्वाचित स्वायत्त बोर्डों के अधिकारों का हनन कर नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ा रही हैं। नियोजता विवाद को अनसुलझा रखकर प्रशासनिक टालमटोल से त्रिस्तरीय ढांचा पंगु हो रहा है, जिससे स्वायत्तता और लोकतांत्रिक भावना संकट में है।



भारतीय सहकारिता आंदोलन की धुरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिस्वरण तंत्र के रूप में कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स एवं लैम्पस) वर्तमान समय में प्रशासनिक अनिर्णय तथा नौकरशाही की प्राधिकारवादी प्रवृत्ति के कारण गंभीर संस्थागत संकट से जूझ रही हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता के त्रिस्तरीय ढांचे की स्वायत्तता पर मंडराते संकट का मूल कारण वह अंतहीन ‘कमेटी संस्कृति’ है, जिसने जनहितैषी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रशासनिक शिथिलता एवं औपनिवेशिक मानसिकता का बंदी बना दिया है। सैद्धांतिक एवं वैधानिक दृष्टि से यह निर्विवाद सत्य है कि प्राथमिक सहकारी समितियां स्वायत्त निकाय हैं, जिनके कार्मिकों का नियोजता निर्धारण तथा उनकी सेवा शर्तों का विनियमन संबंधित निर्वाचित संचालक बोर्डों का अनन्य क्षेत्राधिकार है। इसके बावजूद विगत एक दशक से नियोजता निर्धारण के नाम पर निरंतर कमेटियों के गठन का जो छद्म प्रपंच रचा जा रहा है, वह वस्तुतः निर्वाचित बोर्डों की संप्रभुता पर प्रशासनिक अतिक्रमण और सहकारिता की आत्मा का हनन है। सहकारिता के मूल दर्शन में विकेंद्रीकरण, स्वशासन तथा अपने सदस्यों के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निहित है। परंतु, विगत वर्षों में प्रशासनिक पदानुक्रम द्वारा कैडर, कॉमन कैडर, नाबार्ड एचआर पॉलिसी तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों की मनमानी नीतियों के नाम पर जो जटिल नियामक ताना-बाना बुना गया है, उसने त्रिस्तरीय सहकारिता



ढांचे के संतुलन को समूल विनिष्ट कर दिया है। निर्वाचित संचालक मंडलों के स्व-निर्णय की मौलिक अधिकारों को प्रशासनिक आदेशों की बेड़ियों में जकड़कर उन्हें निष्प्रभ और अधिकारविहीन कर दिया गया है। कागजी कमेटियों के इस मायाजाल ने पैक्स के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वावलंबन को पूरी तरह पंगु बना दिया है, जिसके फलस्वरूप सहकारिता आंदोलन अपने मूल पथ से विचलित होकर नौकरशाही के नियंत्रण वाली किसी औपनिवेशिक एजेंसी के रूप में परिवर्तित होता प्रतीत हो रहा है। विगत एक दशक का लेखा-जोखा इस तथ्य का प्रमाण है कि पैक्स कार्मिकों की व्यावहारिक समस्याओं तथा नियोजता निर्धारण की जटिलताओं के आवरण में दर्जनों उच्चस्तरीय कमेटियों का सृजन किया गया। इन बैठकों, अध्ययनों और दौरों के नाम पर जनसाधारण के गाढ़े पसीने की कमाई और सहकारी कोष का अनियंत्रित अपव्यय किया गया, किंतु विडंबना यह है कि इनमें से किसी भी समिति की अनुशंसामूलक आख्या को आज तक सार्वजनिक पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह

परिदृश्य प्रशासनिक अपारदर्शिता और अमूल्य संसाधनों की निरर्थक खपत की पराकाष्ठा को रेखांकित करता है। नीतिगत गलियारों की यह अंतहीन लालफीताशाही केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहकारिता विभाग की विकृत हो चुकी कार्यसंस्कृति का परिचायक है। नौकरशाही की इस विसंगतिपूर्ण प्रणाली और सत्तागत संकीर्णता का एक सजीव उदाहरण विभाग के उस वरिष्ठ अधिकारी की प्रशासनिक परिणति में देखा जा सकता है, जो कल तक सहकारिता की दूरगामी नीतियों के निर्धारण में सर्वसर्वा बने हुए थे। प्रशासनिक फेरबदल की एक ही आंधी ने जब उनकी राजनीतिक व प्रशासनिक महत्ता को क्षीण किया, तो उन्हें नीतिगत प्राधिकार के शीर्ष पद से विस्थापित कर गोदाम निर्माण और ईंट-सीमेंट के भौतिक लेखा-जोखा संबंधी अनुभाग में पदस्थापित कर दिया गया। जो अधिकारी कल तक संपूर्ण राज्य के सहकार आंदोलन की दिशा और दशा निर्धारित करने का दंभ भरते थे, वे आज निर्माण कार्यों के जोड़-बाकी में उलझने को अभिशप्त हैं।

सहकारिता विभाग के गलियारों में गुंजता यह व्यंग्य कि “जैसी नीतियां, वैसी ही कार्यशैली का दुष्परिणाम” वस्तुतः इस बात का प्रतीक है कि सहकारिता में दीर्घकालिक चिंतन का अभाव है और पूरी व्यवस्था व्यक्तिगत हित-साधन तथा तदर्थवाद के आधार पर संचालित हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में यदि पैक्स और लैम्पस के निर्वाचित बोर्डों के विधिक प्राधिकार पर आघात इसी भांति अनवरत जारी रहा और बाह्य प्रशासनिक दबावों द्वारा कैडर-नीतियों को जबरन थोपने का प्रयास होता रहा, तो सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा अपनी लोकतांत्रिक चेतना और जन-संवेदनशीलता को पूर्णतः खो देगा। एक तरफ तो शासन द्वारा पैक्स के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन और कम्प्यूटीकरण के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्मिकों के नियोजता संबंधी आधारभूत विवाद को जानबूझकर अनसुलझा रखकर पूरी व्यवस्था को प्रशासनिक गतिरोध की दलदल में धकेला जा रहा है। अब समय आ गया है कि सहकारिता महकमा और शासन कागजी कमेटियों के इस निरर्थक प्रहसन का अविलंब समापन करें। त्रिस्तरीय ढांचे में व्याप्त असंतुलन को समाप्त करने हेतु यह अपरिहार्य है कि निर्वाचित संचालक मंडलों को उनके वास्तविक स्वायत्त अधिकार पुनः सौंपे जाएं, ताकि सहकारिता का यह ऐतिहासिक आंदोलन नौकरशाही की फाइलों के मकड़जाल से मुक्त होकर किसानों, ग्रामीणों एवं आमजन की सेवा में अपनी पूर्ण लोकतांत्रिक सामर्थ्य के साथ पुनः प्रतिष्ठित हो सके। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

जय हिन्द

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

सिंवानी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सिंवानी

पंचायत समिति - सिंवानी, जिला - बालोतरा

मनोहर सिंह भायल

अध्यक्ष

भवानीसिंह राजपुरोहित

उपाध्यक्ष

पीरसिंह राजपुरोहित

व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

हमारी सेवाएं

कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

जय हिन्द

सांवरीज बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सांवरीज

पंचायत समिति - फलोदी, जिला - फलोदी

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

पप्पूराम गोदारा

मुख्य व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

रमेश कुमार

मुख्य व्यवस्थापक

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

जय हिन्द

पावटा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पावटा

पंचायत समिति - आहोर, जिला - जालोर

नरेन्द्रसिंह बालोत

अध्यक्ष

भागीरथसिंह राजावत

व्यवस्थापक

विक्रमसिंह बालोत

उपाध्यक्ष

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

हमारी सेवाएं

किसानों के लिए राज्य सरकार की योजना के तहत ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण की सुविधा उपलब्ध

वरीगाराम विश्वोई से लेकर हनुमानसिंह राजावत तक: जालोर जिला पैक्स व्यवस्थापक यूनियन का स्वर्णिम सफर, संघर्ष और वर्तमान कार्य-परिदृश्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जालोर। पश्चिम राजस्थान की धवल मरुधरा, ग्रेनाइट नगरी और ऐतिहासिक विरासत से सुसज्जित जालोर जिला अपनी अनूठी भौगोलिक एवं कृषि-जलवायुकि विशेषताओं के लिए पूरे प्रदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। यहां के पैक्स और लैम्पस कर्मियों के अधिकारों, संगठन के सुदृढीकरण तथा सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जालोर जिला पैक्स व्यवस्थापक यूनियन का इतिहास बेहद संघर्षशील और प्रेरणादायी रहा है। वर्ष 1977 में रोपी गई सहकारिता संगठन की यह पौध आज एक मजबूत वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसके सफर में कई नेतृत्वकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जालोर जिले की भौगोलिक बनावट बेहद विविध है। अरावली पर्वतमाला की छिटपुट श्रृंखलाएं और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ (जिन्हें सुंधा माता पर्वत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है) इस क्षेत्र के भू-दृश्य को अनूठा बनाती हैं। जिले की मुख्य जीवनदायिनी नदी लूनी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ (जैसे सुकड़ी, जवाई, खारी और बांडी) इस भू-भाग से गुजरती हैं, जो यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि की रीढ़ हैं। अरावली के आंचल से निकलने वाली इन नदियों के बहाव क्षेत्र के आसपास की उपजाऊ भूमि पर

यहाँ के किसान पारंपरिक खेती करते हैं। कृषि-जलवायु खंड के दृष्टिकोण से जालोर शुष्क एवं अर्ध-शुष्क संक्रांति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ बाजरा, ज्वार, इसागोल (साइलियम भूसी), जीरा, कपास, मूंग और सरसों की बंपर पैदावार होती है। कृषि आधारित इस अर्थव्यवस्था में किसानों को समय पर खाद, बीज और ऋण उपलब्ध कराने में पैक्स और लैम्पस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचा सक्रिय है—शीर्ष स्तर पर अपेक्स बैंक (राजफैड/कोऑपरेटिव बैंक), मध्यवर्ती स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और आधार स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स एवं लैम्पस कार्यरत हैं। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी ग्रामीण स्तर के पैक्स हैं, जिनका संचालन व्यवस्थापक और कार्मिक करते हैं। वर्ष 1977 से जालोर जिले में कार्यरत सहकारी समितियों के पैक्स कर्मियों के हितों, संगठन एकीकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ‘व्यवस्थापक यूनियन’ की नींव रखी गई। जब पहली बार जालोर में संगठन की पहल हुई, तो पैक्स कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मजबूत जिला संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप जालोर जिला व्यवस्थापक यूनियन का औपचारिक गठन किया गया।

वारीगाराम विश्वोई

(1977 से 1984)

उदयसिंह देवड़ा

(1985 से 1987)

आदाराम लुकड़ा

(1987 से 1989)

अमरसिंह राठौड़

(1989 से 1996)

हुकमसिंह राठौड़

(1997 से 2017)

भागचंद विश्वोई

(2017 से 2019)

हनुमानसिंह राजावत

(2019 से वर्तमान)

[सबसे लंबा कार्यकाल – 20 वर्ष]

वर्ष 1977 से लेकर अब तक यूनियन के अध्यक्ष पद पर कई दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्वकर्ताओं ने कार्य किया है, जिनके कार्यकाल का संक्षिप्त लेखा-जोखा इस प्रकार है:

- वारीगाराम विश्वोई (1977 से 1984): यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष; संगठन की नींव रखी और शुरुआती एकता स्थापित की।
- उदयसिंह देवड़ा (1985 से 1987): संगठन को शुरुआती दौर में मजबूती प्रदान की और प्रशासनिक स्तर पर आवाज उठाई।
- आदाराम लुकड़ा (1987 से 1989): कार्मिकों की सेवा शर्तों और समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष किया।
- अमरसिंह राठौड़ (1989 से 1996): लगभग 7 वर्षों तक नेतृत्व कर यूनियन को एक नई दिशा दी।
- हुकमसिंह राठौड़ (1997 से 2017): सबसे लंबा कार्यकाल (20 वर्ष); इतिहास में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहकर सहकार जगत से अछूटे आमजन को एक साथ खींचा।
- भागचंद विश्वोई (2017 से 2019): युवा ऊर्जा के साथ कार्मिकों के हितों की पैघवी की और संगठन को गति दी।
- हनुमानसिंह राजावत (2019 से वर्तमान): जिला स्तर से लेकर प्रांतीय (प्रदेश) स्तर तक शानदार नेतृत्व, नीति-निर्धारक भूमिका और ऐतिहासिक संघर्ष।

विशेष कीर्तिमान:

जालोर जिला व्यवस्थापक यूनियन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक (लगभग 20 वर्षों तक, 1997 से 2017 तक) अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड हुकमसिंह राठौड़ के नाम दर्ज है, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को ग्रामीण आंचल की गहराइयों तक पहुंचाया।

एक्सपर्ट व्यू - सहकारिता की नई ऊंचाइयों

वरीगाराम विश्वोई द्वारा 1977 में जलाई गई सहकारिता संघर्ष की मशाल आज हनुमानसिंह राजावत के ओजस्वी नेतृत्व में और अधिक प्रखर हो चुकी है। पुराने नेतृत्व के त्याग, तात्पर्य और समर्पण की नींव पर खड़े वर्तमान नेतृत्व ने पैक्स आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जालोर जिले का यह सहकार सफर इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व निष्ठावान, संघर्षशील और नीति-कुशल हो, तो कठिन से कठिन प्रशासनिक चुनौतियों को भी सकारात्मक पहलों में बदला जा सकता है।

व्यवस्थापक यूनियन नेतृत्व का संघर्ष, व्यावहारिक नीतिगत निर्णय एवं वर्तमान कार्य-परिदृश्य

सहकारिता क्षेत्र में पैक्स-लैम्पस कार्मिक और व्यवस्थापक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। किसानों को खाद-बीज वितरण, अल्पकालीन ऋण प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन में इनकी भूमिका सर्वोपरि है। हालांकि, लंबे समय तक पैक्स कार्मिकों को उचित वेतनमान, जॉब सिक्योरिटी और प्रशासनिक संरक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवस्थापक यूनियन के नेतृत्व ने हमेशा संघर्ष का मार्ग चुना। पूर्ववर्ती नेतृत्व से लेकर वर्तमान नेतृत्व तक, यूनियन ने शासन-प्रशासन के साथ संवाद और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन के माध्यम से व्यावहारिक नीतिगत निर्णय करवाए। पैक्स कार्मिकों के सेवा नियमों को दुरुस्त करवाने, समय पर वेतन भुगतान और मानदेय विसंगतियों को दूर करने में यूनियन के संघर्ष ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

वर्तमान नेतृत्व: हनुमानसिंह राजावत का प्रांतीय स्तर पर विजन, संघर्ष और मान-सम्मान

वर्ष 2019 से जालोर जिला पैक्स व्यवस्थापक यूनियन की कमान संभाल रहे हनुमानसिंह राजावत ने अपने कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व से न केवल जालोर जिले में बल्कि पूरे राजस्थान (प्रांतीय स्तर) पर व्यवस्थापक यूनियन का मान-सम्मान कई गुना बढ़ा दिया है। उनके नेतृत्व में यूनियन ने स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर प्रांतीय स्तर पर नीति-निर्धारक की भूमिका निभाई है।

राजावत के नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं

- प्रांतीय स्तर पर मुखर पैघवी: प्रदेश भर के पैक्स-लैम्पस कार्मिकों के अधिकारों, कैडर रिब्यू, और पारदर्शी नीति-निर्धारण के लिए जयपुर से लेकर जिला मुख्यालयों तक सशक्त आवाज बुलंद की है।
- व्यावहारिक नीतिगत निर्णय: शासन के उच्च स्तर पर सहकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्मिकहित में कई व्यावहारिक नीतिगत बदलाव और निर्णय लागू करवाए हैं।
- कर्मचारियों का हक और सुरक्षा: पैक्स कार्मिकों की जॉब सिक्योरिटी, पेंशन/ग्रेजुएटी और वित्तीय सुरक्षा के मुद्दों पर ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व किया है।
- यूनियन की गरिमा और प्रतिष्ठा: जालोर जिले के सहकारिता इतिहास में यूनियन को एक सम्मानित और अनुशासित संगठन के रूप में स्थापित किया है, जिससे प्रदेशभर में जालोर का नाम रोशन हुआ है।



जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन

सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने ली केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक; कोटा सीसीबी को मिला पहला स्थान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। नेहरू सहकार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सहकारिता में सहकार, राज्य सरकार की बजट घोषणाएं, 1949 एक्ट की पालना आदि कार्यों की समीक्षा की गई है। डॉ. शर्मा कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जन विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य तय करना चाहिए एवं लक्ष्यों के विरुद्ध प्रतिमाह आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश



एनपीए नियंत्रण और ग्राहक सेवा में सुधार

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा सहकार से समृद्धि के तहत किये जा रहे कार्य यथा पैक्स का कम्प्यूटाइजेशन, पैक्स के व्यवसाय के विविधिकरण करने, एम-पैक्स में नये सदस्य बनाने, उन्हें ऋण वितरण करने, आई4सी और सीजीटीएमएसई की सदस्यता, सहकारिता में सहकार योजना के तहत दुग्ध उत्पादक समितियों के सहकारी बैंकों में खाते खोलने, बैंक मित्र बनाने, माइक्रो एटीएम के माध्यम से डोर-स्टेप बैंकिंग की सुविधा देने बजट घोषणा में फसली ऋण वितरण, गोपाल क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायक समूहों सहित अन्य बैंकिंग एक्टिविटीज की समीक्षा की। शासन सचिव, सहकारिता ने बैठक में बताया कि समस्त ऋणी कृषकों का फसल बीमा 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी एम-पैक्स पर सीएचसी, पीएमकेएसके आदि समस्त सेवाएं सुचारू एवं त्वरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों को एनपीए के स्तर को कम से कम करने तथा कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

प्रदान किए। साथ ही समस्त बैंकों एवं उनकी शाखाओं के कार्मिकों को ईबीएएस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कर नियमित रूप से उपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों

के कार्यों के प्रभावी निष्पादन को केपीआई के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इनका उद्देश्य कार्यालयों, शाखाओं एवं उनके क्षेत्राधीन पैक्स के सुशासन, वित्तीय अनुशासन,

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, शिकायत निस्तारण, विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करना है। केपीआई (की-परफोरमेंस-इण्डिकेटर्स) के

आधार पर सीसीबी बैंक एवं उनकी शाखाओं को रैंकिंग दी गई है। बैंकों की रैंकिंग में कोटा सीसीबी प्रथम स्थान पर, झालावाड़ सीसीबी द्वितीय स्थान पर एवं भीलवाड़ा सीसीबी तृतीय स्थान पर रहा।

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

चान्दुर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. चान्दुर
पंचायत समिति - जसवंतपुरा, जिला - जालोर

खुशवीरसिंह अध्यक्ष
भगवतसिंह उपाध्यक्ष
तलकाराम व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

ओड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ओड़ा
पंचायत समिति - शिवगंज, जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

तन सिंह अध्यक्ष
खीव सिंह उपाध्यक्ष
भोपाल सिंह मुख्य व्यवस्थापक
फूलाराम मेघवाल सहायक व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

परमानंद पुरोहित अध्यक्ष
मुणाराम रांगी उपाध्यक्ष
जेलाराम व्यवस्थापक

बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिकवाड़ा
पंचायत समिति - जसवंतपुरा, जिला - जालोर

समस्त किसान भाईयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

कोरणा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सवाईराम अध्यक्ष
शैतान देवारी व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बुड़ीवाड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

राणसिंह अध्यक्ष
छगनाराम व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

लक्ष्मी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नारादरा

पंचायत समिति - सिरोही, जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्रीमती उषा कंवर अध्यक्ष
भोपाल सिंह राठौड़ व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

सोरड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सोरड़ा
पंचायत समिति - रेवदर , जिला - सिरोही

गणेशाराम उपाध्यक्ष
रुद्राराम देवासी सहा. व्यवस्थापक
दानाराम चौधरी अध्यक्ष
नारायणलाल राणा व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चूण्डा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. चूण्डा
पंचायत समिति - आहोर, जिला - जालोर

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

दिनेश कुमार व्यवस्थापक
प्रेम सिंह अध्यक्ष
हनुवन्त सिंह उपाध्यक्ष
पता राम स. व्यवस्थापक

मारवाड़ का मित्र

जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर

मारवाड़ का मित्र
facebook.com/marwarakamitra
visit, Like and share

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

घाणा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. घाणा
पंचायत समिति - आहोर, जिला - जालोर

मानसिंह गौड़ अध्यक्ष
कपूराराम व्यवस्थापक
शुभम दवे स. व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सावीदर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सावीदर
पंचायत समिति - जसवंतपुरा, जिला - जालोर

भनारसिंह अध्यक्ष
नितिराजसिंह भारी व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

किसानों से अपील

किसानों से अपील

किसानों से अपील

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

जैतावाड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जैतावाड़ा
पंचायत समिति - रेवदर , जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

उत्तम कुमार अध्यक्ष
रणजीतसिंह स. व्यवस्थापक
दिनेश कुमार उपाध्यक्ष

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मेर मांडवाड़ा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
पंचायत समिति - सिरोही , जिला - सिरोही

किसानों, ग्रामीणों व सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

गुमान सिंह देवड़ा अध्यक्ष
देवी सिंह देवड़ा स. व्यवस्थापक
झवर सिंह देवड़ा उपाध्यक्ष
बाबू लाल मेघवाल सहायक व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं - मिनी सहकारी बैंक - अल्पकालीन फसली ऋण वितरण - खाद-बीज कीटनाशक विक्रय

महावीरसिंह देवड़ा व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चांदराई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. चांदराई
पंचायत समिति - आहोर, जिला - जालोर

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

जखरसिंह राठौड़ अध्यक्ष
मूलसिंह राठौड़ अध्यक्ष
सुरेश कुमार चौधरी व्यवस्थापक

महावीरसिंह - सहा. व्यवस्थापक
खीमाराम - सहायक व्यवस्थापक
परवतसिंह, परकरसिंह, महावीरसिंह, अशोक कुमार, कालुलाल, टिकमाराम, चंदा, पवन

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

कैलाशनगर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
पंचायत समिति - शिवगंज , जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्री ईश्वरसिंह अध्यक्ष
श्री प्रवीण कुमार उपाध्यक्ष

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्री ईश्वरसिंह देवड़ा मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

जालोर में भी लागू हो सिरोही जैसी व्यवस्था: पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों ने ब्याज विसंगतियों दूर करने की उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) और लैम्पस की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने रुख अपनाया है। यूनियन ने जिला प्रशासन और केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन से मांग की है कि दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तर्ज पर जालोर में भी ब्याज रिवर्सल और अन्य वित्तीय विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल आदेश जारी किए जाएं। यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर, सहकारिता विभाग के अधिकारियों

यूनियन द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें और विसंगतियों का निवारण

- **ब्याज अनुदान का सही अंतरण:** समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों से प्राप्त होने वाली 4 प्रतिशत ब्याज सहायता राशि में से 2 प्रतिशत राशि संबंधित पैक्स/लैम्पस के बचत खातों में समय पर जमा करवाई जाए।
- **चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक:** वित्तीय वर्ष के अंत यानी 31 मार्च और 30 जून को समितियों के पक्ष में बकाया ब्याज को मूलधन में जोड़कर 'ब्याज पर ब्याज' वसूलने की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
- **केआरपी पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि:** पैक्स और लैम्पस स्तर पर KRP पोर्टल पर सभी सदस्यों के PIR एवं IS क्लेम तथा O4 प्रतिशत ब्याज अनुदान क्लेम समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो।

और केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से ब्याज वसूली की विसंगतियों पर फोकस किया गया

है। यूनियन का कहना है कि ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत जिन सदस्यों के अल्पकालीन ऋणों की वसूली समय पर जमा हो जाती

है, उन पर पैक्स/लैम्पस से कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। यदि टीसीएस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमैटिक ब्याज डेबिट कर लिया

जाता है, तो उसे तुरंत रिवर्स किया जाए। पैक्स कर्मचारियों का तर्क है कि सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अपने पत्र के जरिए वहां के पैक्स/लैम्पस के लिए ये स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि समय पर वसूली होने पर समितियों से कोई अतिरिक्त ब्याज न लिया जाए। चूंकि जालोर जिले की समितियां भी इसी त्रिस्तरीय ढांचे के तहत कार्य कर रही हैं, इसलिए यहाँ भी इन विसंगतियों को दूर करना अति आवश्यक है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन बिंदुओं पर स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए, तो समितियों की वित्तीय हालत और अधिक बिगड़ सकती है



‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ से बदलेगी खेतों की तस्वीर

जालोर में कृषि क्रांति: सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मिलेगी आधुनिक मशीनरी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जालोर, कृषि प्रधान जिले जालोर के किसानों के लिए एक बड़ी सीगात आई है। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने जिले में कृषि के आधुनिकीकरण और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जिले की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ‘कस्टम हायरिंग केंद्र’ स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। यह पहल न केवल कृषि की लागत को कम करेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच भी आधुनिक कृषि उपकरणों तक सुनिश्चित करेगी। जालोर का अतीत हमेशा से कृषि और पशुपालन पर आधारित रहा है। जहां पहले किसान पारंपरिक साधनों और उपकरणों पर निर्भर थे, वहीं बदलते दौर में अब तकनीकी का समावेश आवश्यक हो गया है। कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना इस बदलाव की कड़ी है। इन केंद्रों के जरिए किसान अब महंगे कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर और सीड ड्रिल किराए पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें खेती की मशीनीकरण में आने वाली भारी लागत से मुक्ति मिलेगी। सहकारी



क्या है परियोजना?

कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत इन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसमें 30 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत केंद्रों को तीन माह के भीतर इन यंत्रों की खरीद कर प्रभावी संचालन शुरू करना अनिवार्य होगा।

समितियों का राजस्थान के विकास में हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ‘एक सबके लिए, सब एक के लिए’ के मंत्र पर आधारित हमारा सहकारी आंदोलन आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये ग्राम सेवा सहकारी समितियां अब तक वित्तीय ऋण और खाद-बीज उपलब्ध कराने तक सीमित

थीं, लेकिन अब ये कृषि यंत्रों के प्रबंधन की नई जिम्मेदारी संभालकर किसानों का संबल बनी हैं। इन समितियों के माध्यम से पारदर्शी और भरोसेमंद वित्तीय सेवाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है, जिससे उन्हें साहकारों के चंगुल से दूर रहकर खेती में नवाचार करने का मौका मिल रहा है।

29 सहकारी समितियों पर खुलेंगे कृषि मशीनरी केंद्र

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन केंद्रों से खेती की लागत में कमी आएगी। जालोर की मिट्टी की उर्वरता और किसानों के परिश्रम को आधुनिक मशीनों का साथ मिलने से जिले के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना है, और यह कदम ‘स्मार्ट खेती’ की दिशा को एक नई पहचान दिलाएगा। इस पहल का मुख्य लक्ष्य कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना और लागत में कमी लाना है, जिसके तहत जिले की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन किया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के तीन माह के भीतर इन केंद्रों का संचालन अनिवार्य किया गया है, जिससे भविष्य में सहकारी समितियों की भूमिका और अधिक मजबूत होगी और वित्तीय व तकनीकी सहायता का समावेश हो सकेगा। इस निर्णय से जालोर के कृषि बाहुल्य क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो भविष्य में जिले को उन्नत कृषि के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

नवारा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नवारा

पंचायत समिति - सिरोही, जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

नरपतसिंह
अध्यक्ष

मुकनसिंह देवल
मुख्य व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड आहोर

पंचायत समिति-आहोर, जिला-जालोर

किसानों के लिए उन्नत बीज, खाद, यूरिया एवं डीएपी उर्वरक 24 घंटे उपलब्ध हैं

सूर्यवीरसिंह राठौड़
चेयरमैन केवीएसएस

किसानों व सदस्यों से अपील : अपनी कृषि जिंसी का को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से ही बेचीन करें।

नरेन्द्रसिंह इन्दा (RCS)
मुख्य व्यवस्थापक

राज्यसभा में एनसीडीसी संशोधन विधेयक पास

नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन से संबंधित विधेयक सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। हालांकि, विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष के अधिकांश दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम शुरू हो चुका है और पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश में 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि इन पहलों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का कार्यक्षेत्र बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी पिछले छह दशकों से देशभर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में नई तकनीक, नए कारोबारी मॉडल, मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और लॉजिस्टिक्स के नए अवसर उभर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक बनाना जरूरी है, ताकि आने वाले वर्षों में सहकारी क्षेत्र के विकास को और गति दी जा सके।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मंडिया बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मंडिया

पंचायत समिति - सिरोही, जिला - सिरोही

भगवतसिंह देवड़ा
अध्यक्ष

मुकनसिंह देवल
मुख्य कार्यकारी

हड़मतसिंह देवड़ा
उपाध्यक्ष

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. आदर्श रायपुर

पंचायत समिति - रेवदर, जिला - सिरोही

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

राजुसिंह
व्यवस्थापक

पुष्पेन्द्रसिंह सहा.
व्यवस्थापक

नरपतसिंह
अध्यक्ष

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

दी. बाड़मेर सेन्द्रल को. ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बाड़मेर

प्रधान कार्यालय : महावीर नगर, बाड़मेर फोन : +91-02982-220461, 220345
फैक्स : +91-02982-220461 Email- DCCB.BARMER@RAJASTHAN.GOV.IN

बैंक की प्रमुख योजनाएं

- राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण
- व्यापारिक फर्म की आकस्मिक आवश्यकता हेतु सीसी लिमिटेड सुविधा
- ग्राहकों की जमाएं डिपोजिट इश्योरेन्स गारंटी कॉरपोरेशन से बीमित व सुरक्षित।
- दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण योजना।
- आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण (मोर्गेज) योजना, शिक्षा ऋण, सहकार ग्राम आवास योजना
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठाएं।
- जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर

जितेन्द्र कुमार (RCS)
प्रबंध निदेशक

चिन्मयी गोपाल (IAS)
जिला कलेक्टर व बैंक प्रशासक

बैंक सेवाओं तथा ऋण सुविधाओं की विस्तृत जानकारी हेतु बैंक की निकटतम शाखा में सम्पर्क करें।

समस्त किसान भाईयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

निंबज बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. निंबज

पंचायत समिति - रेवदर, जिला-सिरोही

सुजानसिंह - अध्यक्ष

केवाराम- उपाध्यक्ष

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

चेलाराम राणा
मुख्य कार्यकारी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मोहब्बतनगर

पंचायत समिति - सिरोही, जिला - सिरोही

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व गत वर्षों से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

महीपाल सिंह
अध्यक्ष

दरगाराम उपाध्यक्ष

निरंजन रावल
स. व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

अमृतलाल
मुख्य कार्यकारी

पैक्स कंप्यूटराइजेशन: सहकारिता की रीढ़ को डिजिटल धार, 18 केंद्रीय सहकारी बैंकों के 4,220 पैक्स कार्मिकों के प्रशिक्षण का रास्ता साफ

- त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स-लैम्पस के कार्मिकों के डिजिटल प्रशिक्षण की रूपरेखा जारी
- राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत नाबाई द्वारा 44.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत
- व्यवस्थापक यूनियन के लंबे संघर्ष और प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, सहकारिता विभाग के स्तर पर जगी नई उम्मीदें

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जयपुर, प्रदेश के सहकारी आंदोलन की त्रिस्तरीय ढांचागत व्यवस्था की सबसे मजबूत और बुनियादी इकाई पैक्स एवं लैम्पस को डिजिटल युग के अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना’ के अंतर्गत अब जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पैक्स-लैम्पस कार्मिकों और अधिकारियों को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा जारी कर दी गई है।

इस पहल से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, गतिशीलता और दक्षता के एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। राज्यभर में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पैक्स के स्तर पर व्यवस्थापक यूनियन का संघर्ष लंबा और निरंतर रहा है ! व्यवस्थापक यूनियन नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में पैक्स-लैम्पस कार्मिकों की इस गंभीर आवश्यकता और कार्यक्षेत्र की व्यावहारिक पीड़ा को लगातार उठाया गया। यूनियन के इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज शासन-प्रशासन स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की रूपरेखा को मूर्तरूप दिया गया है, जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना को धरातल पर सार्थक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अतीत में पैक्स और लैम्पस का पूरा कामकाज मैनुअली (पंजियों और बहियों के माध्यम से) संचालित होता था, जिससे किसानों को समय पर ऋण वितरण, खाद-बीज की उपलब्धता और अन्य सहकारिता सेवाओं में कई प्रकार की व्यावहारिक अड़चनों का सामना करना पड़ता था। समय के बदलाव

प्रथम चरण में 4,220 कार्मिकों का होगा प्रशिक्षण, 44.85 लाख रुपए स्वीकृत

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना के अंतर्गत नाबाई के सहयोग से प्रशिक्षण का प्रथम चरण शुरू कर दिया गया है।

- स्वीकृत राशि:** नाबाई द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 18 केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध 4,483 पैक्स के कुल 4,220 अधिकारियों/कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 44.85,000 की राशि स्वीकृत की गई है।
- प्रमुख केंद्रीय सहकारी बैंक:** इस प्रशिक्षण योजना में बाड़मेर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, दौसा, सिरोही, गंगानगर, टोंक, जालोर, बारों, जोधपुर, नागौर और भरतपुर सहित राज्य के 18 केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल किए गए हैं।
- निर्धारित समयवाधि:** इन सभी बैंकों के अंतर्गत आने वाले पैक्स कार्मिकों का प्रशिक्षण तय तिथियों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन सूचना शीर्ष बैंक के प्रशिक्षण सभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

के साथ सहकारिता के आधुनिकीकरण की मांग उठी और केंद्र सरकार ने देश की पैक्स इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्तमान कार्य-परिदृश्य में, पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के माध्यम से राज्य की सभी पैक्स-लैम्पस शाखाओं

को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को मिलने वाले अल्पकालीन फसली ऋण, उर्वरक वितरण, और अन्य बैंकिंग सेवाओं का रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन हो रहा है।

वेंडर और तकनीकी पक्ष पर फोकस

योजना के वर्तमान क्रियान्वयन में हार्डवेयर संस्थापन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डेटा माइग्रेशन और तकनीकी वेंडर की भूमिका सबसे अहम बनी हुई है। पैक्स स्तर पर कंप्यूटरीकरण के दौरान वेंडर द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं, सॉफ्टवेयर के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करने पर अब विशेष फोकस किया जा रहा है। जब तक पैक्स कार्मिक तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे, तब तक वेंडर द्वारा स्थापित प्रणालियों का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में वेंडर द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर के व्यावहारिक उपयोग और डेटा एंट्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। व्यवस्थापक यूनियन नेतृत्व सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने विश्वास जताया है कि इस डिजिटल प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण आंचल के किसानों को पैक्स के माध्यम से बैंक जैसी आधुनिक डिजिटल बैंकिंग और सहकारिता सुविधाएं घर बैठे और पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सकेंगी।

पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत कार्मिकों को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने की मांग को लेकर सहकारिता विभाग में हमारा संघर्ष लंबा रहा है। जमीनी स्तर के कार्मिकों की इस समस्या पर पैरवी के बाद तैयार की गई प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा सहकारिता जगत में एक सकारात्मक बदलाव और सार्थक पहल है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को मुखरता से उठाने में ‘मारवाड़ का मित्र’ समाचार पत्र की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। इस अखबार ने निरंतर और निष्पक्ष कवरेज के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को प्रमुखता से उठाया।

— सूरजभान सिंह आमेरा एवं हनुमानसिंह राजावत (व्यवस्थापक यूनियन नेतृत्वकर्ता)

स्वतंत्रता दिवस, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चित्तलवान जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित। संपादक। मो. 9602473302। नोट: पीआरटी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी। (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक ‘मारवाड़ का मित्र’ किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा।